भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3297
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में कुपोषण

3297. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:
डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और रक्ताल्पता के संबंध में, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण जिलों में, जिला-वार कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत उपयोग में कमी की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि देश में कुपोषण की समस्या से निपटने की दृष्टि से पोषण अभियान की प्रासंगिकता संतोषजनक है।

वर्ष 2021 में विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों में पोषण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण कराया गया था। राज्यों का चयन बच्चों में बौनापन तथा महिलाओं में एनीमिया की उच्च व्याप्तता के आधार पर किया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पोषण अभियान के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में पोषण संबंधी व्यवहारों में सुधार हुआ। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे तथा 81% महिलाओं ने जन्म के पश्चात प्रथम छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराया।

विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)), नीति आयोग (2025) द्वारा पुनः मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) का परिणाम-आधारित

मूल्यांकन अध्ययन 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश सहित) एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में किया गया। साक्ष्य दर्शाते हैं कि अपने वर्तमान स्वरूप में, मिशन पोषण 2.0 कुपोषण के समग्र उन्मूलन एवं बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नवीनतम प्रयास है, जिसे विगत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तालमेल एवं सुदृढ़ दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है। पूरक पोषण, वृद्धि निगरानी एवं परामर्श जैसी आंगनवाड़ी सेवाओं की उच्च स्वीकार्यता एवं उपयोग किया जाना इस बात का ठोस संकेत है कि पोषण अभियान जागरूकता उत्पन्न करने एवं लाभार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी एवं समीक्षा हेतु 'पोषण ट्रैकर' नामक डिजिटल एप्लीकेशन को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित निगरानी उपकरण के रूप में शुरू किया है। इस एप्लीकेशन ने मंत्रालय के साथ-साथ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति सहित योजना के कार्यान्वयन की विभिन्न मानकों पर समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में समर्थ बनाया है। अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की निगरानी के उद्देश्य से टेक होम राशन के वितरण के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल एप्लीकेशन में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही प्रदान किया जाता है। आधार आधारित इस प्रकार की निगरानी से लाभार्थियों की समुचित पहचान, दुरूपयोग को कम करना एवं फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त करना संभव हुआ है।

*****